vinetur

फ्रांस की सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत ने Graves वाइन के लिए अनिवार्य सामूहिक लेबल को बरकरार रखा

अदालत ने UMVIN की चुनौती खारिज की ; 2026 की फसल से बनी Graves वाइन की बोतलों पर चार्टर-आधारित पहचान-चिह्न अनिवार्य रहेगा।

बुधवार, 18 नवंबर 2026



फ्रांस की सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत Conseil d'État ने मंगलवार, 17 नवंबर को फैसला सुनाया कि Graves अपीलेशन की वाइनों के लेबल पर सामूहिक पहचान-चिह्न अनिवार्य किया जा सकता है। अदालत ने Union des maisons et marques de vin, यानी UMVIN, की चुनौती खारिज कर दी।

विवाद का केंद्र फ्रांसीसी सरकार की ओर से 2025 में Bordeaux के Graves और Graves Supérieures नियंत्रित अपीलेशनों के उत्पाद विनिर्देशों में मंजूर किए गए बदलाव थे। UMVIN ने अदालत से उन मंत्रिस्तरीय आदेशों को रद्द करने की मांग की थी जिनसे इन विनिर्देशों को मंजूरी मिली थी। वैकल्पिक रूप से, उसने उस प्रावधान को हटाने का अनुरोध किया था

जिसके तहत बोतलों पर Graves वाइन उत्पादकों के संघ द्वारा तैयार चार्टर के अनुरूप सामूहिक पहचान-चिह्न दिखाना अनिवार्य है।

Conseil d'État ने कहा कि 3 मार्च, 2025 के आदेश को बाद में निरस्त कर Graves अपीलेशन से संबंधित 19 सितंबर, 2025 के आदेश से बदल दिया गया था, इसलिए मामले को बाद वाले आदेश के खिलाफ चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने UMVIN के दावों को खारिज कर दिया।

फैसले के अनुसार, Graves के विनिर्देशों में कहा गया है कि 2026 की फसल से वाइन के लेबल पर लागू चार्टर में वर्णित सामूहिक पहचान-चिह्न शामिल होना चाहिए और यह सभी संचालकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। अदालत ने कहा कि इस भाषा को मंजूरी देकर मंत्रियों ने चार्टर की सामग्री को अपीलेशन के विनिर्देशों के भीतर बाध्यकारी नियम का दर्जा दे दिया। इस पहचान-चिह्न में अन्य तत्वों के साथ, बड़े अक्षरों में "Graves" शब्द वाला लोगो शामिल है ; संबंधित वाइन के आधार पर इसके नीचे "Vin de Bordeaux" या "Grand vin de Bordeaux" लिखा होता है।

UMVIN ने दलील दी थी कि इस नियम तक पहुंचने की प्रक्रिया कई आधारों पर त्रुटिपूर्ण थी। समूह के अनुसार, राष्ट्रीय आपत्ति प्रक्रिया शुरू करने की सूचना दोषपूर्ण थी, क्योंकि उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि प्रस्तावित बदलावों में बोतलों के लेबल पर सामूहिक पहचान-चिह्न अनिवार्य करना भी शामिल है। Conseil d'État ने इस दलील से असहमति जताई। अदालत ने कहा कि 17 जनवरी, 2024 को फ्रांस के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित सूचना में प्रक्रिया का उद्देश्य—Graves और Graves Supérieures अपीलेशनों के विनिर्देशों में संशोधन—उचित रूप से बताया गया था और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख भी तय की गई थी। अदालत ने कहा कि कानून के तहत सूचना में लेबलिंग के उस विशिष्ट बदलाव का उल्लेख करना जरूरी नहीं था।

वाइन कारोबारियों के इस संगठन ने National Institute of Origin and Quality, यानी INAO, की संबंधित राष्ट्रीय समिति की संरचना पर भी सवाल उठाया। समिति ने 28 नवंबर, 2024 को मसौदा विनिर्देशों को मंजूरी दी थी। UMVIN ने दलील दी कि मतदान में व्यापारियों की तुलना में उत्पादकों की संख्या अधिक थी। अदालत ने यह दावा भी खारिज कर दिया। उसने कहा कि नियम समिति की समग्र संरचना में क्षेत्रों के बीच संतुलित प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, लेकिन कोरम पूरा होने के बाद सदस्यों के मतदान के नियम इससे नहीं बदलते।

एक अन्य प्रक्रियागत दलील INAO समिति की ओर से प्रस्तावित संशोधनों की जांच के लिए नियुक्त जांच आयोग से जुड़ी थी। UMVIN ने कहा कि जून 2024 में व्यापार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सदस्य के हटने और उनकी जगह किसी को नियुक्त न किए जाने के बाद आयोग में कारोबार और क्षेत्रों की जरूरी विविधता नहीं रह गई थी। Conseil d'État ने कहा कि यह बदलाव आयोग की रिपोर्ट जारी होने से कुछ समय पहले हुआ था, इससे रिपोर्ट की विषयवस्तु प्रभावित नहीं हुई और किसी भी स्थिति में इससे अंतिम फैसले पर असर नहीं पड़ सकता था या संबंधित पक्षों को प्रक्रियागत सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता था।

फैसले में फ्रांस के कदमों और यूरोपीय संघ की प्रक्रियाओं के बीच संबंध पर भी विचार किया गया। 2025 के सुधारों के एक हिस्से में Graves Supérieures अपीलेशन को समाप्त करना शामिल था, जिसके लिए यूरोपीय आयोग की मंजूरी जरूरी थी। UMVIN ने दलील दी कि 19 सितंबर, 2025 का आदेश गैरकानूनी था, क्योंकि आयोग के निर्णय से पहले ही उसने इस समाप्ति से जुड़े बदलावों को मंजूरी दे दी थी। Conseil d'État ने यह दलील खारिज करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ के नियमों के तहत आयोग का निर्णय राष्ट्रीय मंजूरी आदेश से पहले आना जरूरी नहीं था। अदालत ने ध्यान दिलाया कि फ्रांसीसी आदेश में ही कहा गया था कि वह अपीलेशन रद्द करने के अनुरोध को आयोग की मंजूरी मिलने की तारीख से ही लागू होगा।

UMVIN ने यह भी कहा कि सितंबर 2025 का आदेश अपनाने से पहले दूसरी राष्ट्रीय आपत्ति प्रक्रिया होनी चाहिए थी। अदालत ने कहा कि नई प्रक्रिया जरूरी नहीं थी, क्योंकि Graves Supérieures को समाप्त करने का प्रस्ताव मार्च 2025 के आदेश से पहले ही राष्ट्रीय आपत्ति प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किया जा चुका था।

फ्रांस के वाइन क्षेत्र में इस मामले पर करीबी नजर रखी जा रही थी, क्योंकि इसमें परखा गया कि कोई अपीलेशन अपने आधिकारिक विनिर्देशों के जरिए सामूहिक प्रस्तुति के नियम किस हद तक लागू कर सकता है। विवाद Graves से जुड़ा था, लेकिन अन्य अपीलेशनों की वाइनरी, सहकारी समितियों और व्यापारियों पर भी इस फैसले का व्यापक असर हो सकता है, यदि वे इसी तरह के साझा पहचान-चिह्न या ब्रांडिंग साधन अपनाने पर विचार करें। इससे मौजूदा नियामक ढांचे के तहत सामूहिक लेबलिंग की शर्तों का बचाव करने के लिए फ्रांसीसी अपीलेशन निकायों के पास उपलब्ध गुंजाइश भी अधिक स्पष्ट होती है।

Graves के उत्पादकों के लिए तत्काल प्रभाव यह है कि 2026 की फसल से बनी वाइनों के लिए अनिवार्य पहचान-चिह्न लागू रहेगा। इसका मतलब है कि उस विंटेज की बोतलें बाद में बाजार में आने पर इस नियम के दायरे में होंगी, जिनमें 2027 में होने वाली बिक्री भी शामिल है। व्यापारियों और ब्रांड मालिकों के लिए इस फैसले से इस अनिवार्यता को मिली एक बड़ी कानूनी चुनौती दूर हो गई है और इसकी पुष्टि हुई है कि मंजूर चार्टर-आधारित पहचान-चिह्न अपीलेशन के लेबलिंग नियमों का हिस्सा बना रह सकता है।